भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 558
दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तर देने के लिए

वैश्विक भुखमरी सूची में भारत की स्थिति

558. श्री डी. राजा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैश्विक भुखमरी सूची (जी.एच.आई.) के नवीनतम संस्करण की ओर गया है जिसमें भारत को 118 देशों में 97वें स्थान पर दर्शाया गया है, जो पिछले वर्ष 104 देशों में 80वें स्थान की तुलना में गिरावट दर्शाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
तथा राज्य मंत्री, शहरी विकास एवं
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने 2016 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत को 118 देशों की सूची में 97वें स्थान पर दर्शाया गया है। जीएचआई रिपोर्ट 2015 में भारत को 104 देशों की सूची में 80वें स्थान पर दर्शाया गया था।

(ख) जीएचआई स्कोर 2016 चार घटक संकेतकों के लिए स्रोत डेटा पर आधारित हैं अर्थात्: (i) अल्पपोषित जनसंख्या का अनुपात, (ii) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में क्षयकारी रोगों की व्यापकता (अर्थात् लम्बाई की तुलना में कम वजन), (iii) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुद्धविकास की व्यापकता (अर्थात् आयु की तुलना में कम लम्बाई), और (iv) पांच वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात। जीएचआई 2016 रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मिश्रित जीएचआई 1992 में 46.4 से सुधर कर 2000 में 38.2 तथा 2008 में और सुधर कर 36.0 और 2016 में 28.5 हो गया है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में वर्ष 2015 के लिए तदनुरूपी सूचकांक 29.0 था जो यह दर्शाता है कि 2016 में भुखमरी सूचकांक में और सुधार हुआ है।

भारत सरकार भुखमरी और कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है और देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों में 50% जनसंख्या को कवर करते हुए राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को अत्यंत इमदादी कीमतों पर खाद्यान्न आबंटित करती है। सरकार अन्य कल्याण स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रही है जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम (आईसीडीएस), वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम, किशोरियों के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम, आपात पोषण कार्यक्रम, आदि।